प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

Consultant (Judicial)
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
प्रधान पीठ, फरीदकोट हाउस,
नई दिल्ली।

पत्रांकः २१ /एम0सी0–खनन अनुभाग/2024 दिनांकः २१ मार्च, 2024

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष योजित Original Application No. 756/2023 सचिन त्यागी बनाम रितेश शर्मा में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के क्रम में प्रेषित नोटिस दिनांक 07.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रकरण के संबंध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 04.03.2024 में सुनवाई की अग्रिम तिथि 14.05.2024 से एक सप्ताह पूर्व आख्या प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण पीठ नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत Originonal Application No. 756/2023 Sachin Tyagi Versus Ritesh Sharma में निम्न आदेश दिनांक 04.03.2024 को पारित किया हैः–

1. In this original application, registered on the basis of the letter petition, allegation is that one contractor Mr. Ritesh Sharma and his a/colleague Kuldeep, residents of Bilaspur, District Panipat, Haryana along with the other persons had started illegal mining of sand from the bed of Mriver Yamuna by using the JCB machines and dumpers and had stocked the illegally mined sand in front of Gaon Garhi Kewal at Hathwala road. It was alleged that on account of said illegal mining the flow of river Yamuna was diverted.

2. Considering the grievance raised in the letter petition, Tribunal on 04.01.2024 had formed a joint committee with the direction to carry out spot inspection, ascertain the extent of illegal mining and persons responsible for the same and suggest remedial measures.

3. Joint committee has filed the status report disclosing as under:-

"3. The joint committee consisting of Secretary, Regional Transport Authority (RTA), Panipat, Regional Officer,
HSPCB, Panipat, Executive Engineer, Irrigation, W/S, Panipat, DSP, (Enforcement), Panipat and Mining Officer, Panipat inspected the site on 22.02.2024.

4. During inspection it was found that mining was being done in the river Yamuna bed by the unit M/s Royal Construction Company, Village Chhapraula, Khadar, Tehsil Baraut, Distt. Bagpat by using JCB machines. The area where the mining is being done falls in the jurisdiction of State of Uttar Pradesh and not falls in the jurisdiction of State of Haryana. A report from Naib- Tehsildar, Samalkha was also obtained to ascertain the area of jurisdiction where mining is being done in the River bed. As per report no. 1229 dated 22.02.2024 given by Naib Tehsildar, Panipat it has been informed the points A, B, C, D shown in the map attached with the report where the mining is in operation during inspection by the joint committee does not falls in the jurisdiction of village Hathwala, Tehsil Samlakha, Dsitrict Panipat. Therefore, the mining area not relates to Village Hathwala. The copy of report is attached as Annexure- B. As such, the area marked as ABCD falls outside the administrative jurisdiction of Distt. Panipat Haryana.

.....क्रमशः 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

5. As per order of Hon'ble High Court of Punjab & Haryana no one can trespass the river bed for transportation of mineral, see order Joginder v/s State of Haryana. Moreover, as per terms & conditions of E.C. mineral concession holder can't use village road for transportation of mineral up to 200n mtrs. of periphery of village abadi."

4. The above report clearly reveals that during the inspection, joint committee had find mining on the river bed of river Yamuna by using JCB machines.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के अनुपालन में जनपद–बागपत की तहसील–बडौत स्थित ग्राम–छपरौली खादर में यमुना नदी में अवैध वालू खनन शिकायत के सम्बन्ध में जॉच उपजिलाधिकारी बडौत, सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ, खान निरीक्षक, बागपत, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक (सर्वे) छपरौली एवं सर्वे लेखपाल ग्राम–छपरौली द्वारा दिनांक 13.03.2024 **(संलग्नक–1)**को की गई। जॉच टीम द्वारा प्रस्तुत आख्या निम्नवत हैः–

01– जनपद–बागपत की तहसील बडौत स्थित ग्राम–छपरौली खादर के यमुना नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू के खनन क्षेत्रों के शासनादेश संख्या 1875/86–2017–57(सा0) 2017 टीसी–1 दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई–निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत, जनपद–बागपत की तहसील बडौत स्थित ग्राम–छपरौली खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 9.570 है0 में साधारण बालू का खनन पट्टा दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 24.10.2028 तक Royal Construction Company Devipura 2 bulandshahar 203001 प्रो0 श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र हरस्वरूप, निवासी मकान नं0–5, नई ब्रेक पाइंट रेस्टोरेन्ट, भूर चौराहा के पास यमुनानगर, बुलन्दशहर के पक्ष में स्वीकृत है।**(संलग्नक–2)**

02– ग्राम–छपरौली खादर में यमुना नदी की जलधारा को न तो रोका गया और न ही परिवर्तित किया जाना पाया गया।

03– जॉच में पट्टेदार द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में बालू का खनन/परिवहन किया जा रहा है।

04– पट्टेधारक द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बालू को वाहनो में भरने(लोडिंग) के लिए मशीनो का प्रयोग किया जा रहा है।

05– ग्राम–छपरौली खादर में स्वीकृत खनन पट्टे हेतु State level Environment Impact Assissment Authority, Uttar Pradesh के Reference-MoEFCC Proposal no SIA/UP/Min/439838/2023 & SEIAA,U.PFile no.-8077/7633 दिनांक 07.10.2023 **(संलग्नक–3)** द्वारा निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–4 Salient features of the project as submitted by the project proponent के बिन्दु संख्या–20–Method of Mining में Open Cast Semi-Mechanized Method का उललेख है तथा उ0प्र0 उपखनिज परिहान नियमावली 2021 के नियम–41(ग) **(संलग्नक–4)** में प्राविधानिक है।"पट्टेदार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार नदी की जलधारा को छोडकर मशीन की सहायता से खनन कर सकता है और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए भी मशीन का प्रयोग कर सकता है।"

06– पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत पटटा क्षेत्र से बालू खनन कर प्रयोग किये जा रहे परिवहन मार्ग में पानी का छिडकाव किया जा रहा है।

07– सर्वे लेखपाल द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा **(संलग्नक–5)** में उलिलखित किया गया है कि ग्राम छपरौली खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 9.570 हे0 में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बिन्दु A,

.....क्रमशः 3 पर

Scanned with OKEN Scanner

B, C, D है। पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र बिन्दु A, B, C, D के अन्दर बालू खनन/परिवहन किया जा रहा है। वर्तमान में यमुना नदी की धारा से B बिन्दु लगभग 20 मीटर तथा C बिन्दु लगभग 15 मीटर की दूरी पर है। नदी की धारा को न तो रोका गया है और न ही परिवर्तित किया गया है।

महोदय उपर्युक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के क्रम में प्रेषित नोटिस दिनांक 07.03.2024 के क्रम में अद्यतन अनुपालन आख्या कृपया अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

21.03.2024

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी,
बागपत।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः— 01— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री मुकेश वर्मा, स्थायी अधिवक्ता मा0 एन0जी0टी0 को अपने स्तर से भी उपरोक्त प्रकरण में प्रभावी पैरवी के संबंध में अनुरोध करने का कष्ट करें।

02— श्री मुकेश वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ओ0ए0 सं0 756/2023 में प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।

03— खान निरीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0 जी0टी0 से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागपत।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-01

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बागपत।

महोदय,

जॉच आख्या

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण पीठ नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत Originonal Application No. 756/2023 Sachin Tyagi Versus Ritesh Sharma में निम्न आदेश दिनांक 04.03.2024 को पारित किया है:–

1. In this original application, registered on the basis of the letter petition, allegation is that one contractor Mr. Ritesh Sharma and his colleague Kuldeep, residents of Bilaspur, District Panipat, Haryana along with the other persons had started illegal mining of sand from the bed of river Yamuna by using the JCB machines and dumpers and had stocked the illegally mined sand in front of Gaon Garhi Kewal at Hathwala road. It was alleged that on account of said illegal mining the flow of river Yamuna was diverted.

2. Considering the grievance raised in the letter petition, Tribunal on 04.01.2024 had formed a joint committee with the direction to carry out spot inspection, ascertain the extent of illegal mining and persons responsible for the same and suggest remedial measures.

3. Joint committee has filed the status report disclosing as under:-

"3. The joint committee consisting of Secretary, Regional Transport Authority (RTA), Panipat, Regional Officer,
HSPCB, Panipat, Executive Engineer, Irrigation, W/S, Panipat, DSP, (Enforcement), Panipat and Mining Officer, Panipat inspected the site on 22.02.2024.

4. During inspection it was found that mining was being done in the river Yamuna bed by the unit M/s Royal Construction Company, Village Chhapraula, Khadar, Tehsil Baraut, Distt. Bagpat by using JCB machines. The area where the mining is being done falls in the jurisdiction of State of Uttar Pradesh and not falls in the jurisdiction of State of Haryana. A report from Naib- Tehsildar, Samalkha was also obtained to ascertain the area of jurisdiction where mining is being done in the River bed. As per report no. 1229 dated 22.02.2024 given by Naib Tehsildar, Panipat it has

Scanned with OKEN Scanner

been informed the points A, B, C, D shown in the map attached with the report where the mining is in operation during inspection by the joint committee does not falls in the jurisdiction of village Hathwala, Tehsil Samlakha, Dsitrict Panipat. Therefore, the mining area not relates to Village Hathwala. The copy of report is attached as Annexure- B. As such, the area marked as ABCD falls outside the administrative jurisdiction of Distt. Panipat Haryana.

5. As per order of Hon'ble High Court of Punjab & Haryana no one can trespass the river bed for transportation of mineral, see order Joginder v/s State of Haryana. Moreover, as per terms & conditions of E.C. mineral concession holder can't use village road for transportation of mineral up to 200n mtrs. of periphery of village abadi."

4. The above report clearly reveals that during the inspection, joint committee had find mining on the river bed of river Yamuna by using JCB machines.

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, बागपत के पृष्ठांकन संख्या 482/एसटी–कैम्प/2024 के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बागपत के पत्र संख्या 375/एसटीएफ/2024 दिनांक 12.03.2024 के क्रम में दिनांक 13.03.2024 को जनपद–बागपत की तहसील–बडौत स्थित ग्राम–छपरौली खादर में यमुना नदी में अवैध बालू खनन शिकायत के सम्बन्ध में जॉच की गई। जॉच आख्या निम्नवत है:–

01– जनपद–बागपत की तहसील बडौत स्थित ग्राम–छपरौली खादर के यमुना नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू के खनन क्षेत्रों के शासनादेश संख्या 1875/86–2017–57(सा0) 2017 टीसी–1 दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई–निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत, जनपद–बागपत की तहसील बडौत स्थित ग्राम–छपरौली खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 9.570 है0 में साधारण बालू का खनन पट्टा दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 24.10.2028 तक Royal Construction Company Devipura 2 bulandshahar 203001 प्रो0 श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र हरस्वरूप, निवासी मकान नं0–5, नई ब्रेक पाइंट रेस्टोरेन्ट, भूर चौराहा के पास यमुनानगर, बुलन्दशहर के पक्ष में स्वीकृत है।

02–ग्राम–छपरौली खादर में यमुना नदी की जलधारा को न तो रोका गया और न ही परिवर्तित किया जाना पाया गया।

03–जॉच में पट्टेदार द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में बालू का खनन/परिवहन किया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

04–पट्टेधारक द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बालू को वाहनो में भरने(लोडिंग) के लिए मशीनो का प्रयोग किया जा रहा है।

05–ग्राम–छपरौली खादर में स्वीकृत खनन पट्टे हेतु State level Environment Impact Assissment Authority, Uttar Pradesh के Reference-MoEFCC Proposal no SIA/UP/Min/439838/2023 & SEIAA,U.PFile no.-8077/7633 दिनांक 07.10.2023 द्वारा निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–4 Salient features of the project as submitted by the project proponent के बिन्दु संख्या–20–Method of Mining में Open Cast Semi-Mechanized Method का उललेख है तथा उ0प्र0 उपखनिज परिहान नियमावली 2021 के नियम–41(ग) में प्राविधानिक है।"

पट्टेदार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार नदी की जलधारा को छोडकर मशीन की सहायता से खनन कर सकता है और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए भी मशीन का प्रयोग कर सकता है।

06–पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत पटटा क्षेत्र से बालू खनन कर प्रयोग किये जा रहे परिवहन मार्ग में पानी का छिडकाव किया जा रहा है।

07–सर्वे लेखपाल द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में उलिलखित किया गया है कि ग्राम छपरौली खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 9.570 हे0 में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बिन्दु A, B, C, D है। पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र बिन्दु A, B, C, D के अन्दर बालू खनन/परिवहन किया जा रहा है। वर्तमान में यमुना नदी की धारा से B बिन्दु लगभग 20 मीटर तथा C बिन्दु लगभग 15 मीटर की दूरी पर है । नदी की धारा को न तो रोका गया है और न ही परिवर्तित किया गया है।

अतः प्रकरण के संबंध में सर्वे लेखपाल द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा/फोटोग्राफ सहित जॉच आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक–01 सर्वे लेखपाल/कानूनगो की रिपोर्ट मय नजरीनक्शा
02 लीज डीड बाबत पट्टा दिनांकित 25.10.2023 की छायाप्रति।

मनू
क्षेत्रीय सर्वे लेखपाल,
ग्राम छपरौली।

क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक(सर्वे)
छपरौली।
नन्द किशोर
सर्वे कानूनगो

खनन निरीक्षक
बागपत

AEE
सहायक अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ।

9/23/24
उपजिलाधिकारी,
बडौत।

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट

महोदय,

रॉयल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी देवीपुरा बुलन्द शहर पिन 203131 के क्रम में सादर यह अवगत कराना है, कि शिकायत कर्ता सचिन त्यागी निवासी ग्राम हथवाला जिला पानीपथ हरियाणा द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण पीठ नई दिल्ली के समक्ष शिकायत की गई थी जिसमे शिकायत कर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत यमुना नदी के जल धारा के साथ-साथ छेड़-छाड़ के साथ-साथ अवैध खनन भी दर्शाया गया है।

उक्त के अनुक्रम मे सादर पटल यह अवगत कराना है कि संयुक्त जाँच टीम ने सर्व प्रथम अवैध खनन के सम्बन्ध मे जाँच की गई व सम्पूर्ण अभिलेखों का अध्ययन किया गया तो भारत सरकार के उपक्रम MSTC द्वारा ई-निविदा के माध्यम से 2023 मे छपरौली खादर गाटा संख्या 1/2 जो तहसील बड़ौत जिला बागपत उ०प्र०

बागपत द्वारा रॉयल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी देवीपुरा बुलन्दशहर जिनके प्रो० दयाचन्द बरगोती को यमुना नदी में साधारण बालू का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। जिसकी छाया कॉपी सलंग्न है।
इसके साथ-साथ जाँच की गई जिसमे स्वीकृत क्षेत्र में A,B,C,D पिलर लगाये गये है तथा पट्टा धारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र मे ही कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ बिन्दु B से वर्तमान मे नदी की जलधारा लगभग 20 मी० की दूरी पर है न तो जलधारा को रोका जा रहा है। और न ही कोई परिवर्तित किया जा रहा है।

सर्वे लेखपाल व सर्वे कानूनगो द्वारा नजरी नक्सा के साथ-साथ जाँच महोदय को सादर प्रेषित है।

सर्वे लेखपाल
सर्वे लेखपाल

सर्वे कानूनगो
नन्द किशोर

सलग्नक-2

12615

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP41149399526001V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP41149399526001V
Certificate Issued Date	:	12-Oct-2023 05:41 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14117604/ BARAUT/ UP-BGH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14117604775824908I3766V
Purchased by	:	ROYAL CONSTRUCTION CO 370737
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	VILLAGE CHHAPRAULI KHADAR TEHSIL BARAUT UTTAR PRADESH KHASRA GATA NO1/2
Consideration Price (Rs.)	:	15,55,72,848 (FifteenCrore Fifty Five Lakh Seventy Two Thousand Eight Hundred And Forty Eight only)
First Party	:	GOVERNOR STATE OF UTTAR PRADESH
Second Party	:	ROYAL CONSTRUCTION CO 370737
Stamp Duty Paid By	:	ROYAL CONSTRUCTION CO 370737
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	31,12,000 (Thirty One Lakh Twelve Thousand only)

Scanned with OKEN Scanner

ई–स्टाम्प सर्टिफिकेट नं0–IN-UP41149399526001V

प्रपत्र–एम.एम. 6

खनन के लिए नीलामी पट्टे का आदर्श प्रपत्र–(नियम 29)

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम–29 के अधीन ई– निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से जिलाधिकारी, बागपत द्वारा साधारण बालू (यमुना नदी) के पट्टा हेतु सहमति पत्रांकः 306/खनन/ई–निविदा सह ई–नीलामी /2022–23 दिनांक 31.12.2022 के कम में

यह अनुबन्ध आज दिन 25-10-2023 दिनांक 24-10-2028 को उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिसे पदावधि के अन्तर्गत यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्ताकिंती भी समझे जायेंगे),

प्रथम पक्ष

ROYAL CONSTRUCTION COMPANY DEVIPURA 2 BULANDSHAHAR-203001 प्रो0 श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र हरस्वरूप, निवासी मकान नम्बर–5, नई ब्रेक पॉइंट रेस्टोरेन्ट भूर चौराहा के पास यमुनापुरम, बुलन्दशहर (व्यक्ति/कम्पनी का नाम, पता और व्यवसाय) जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राहय हो उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

द्वितीय पक्ष

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये ई–निविदा सह–नीलामी के माध्यम से 240000 घनमीटर उपखनिज बालू के लिए पट्टेदार द्वारा अंकन 102/–रूपये प्रति घनमीटर की दर से प्रथम वर्ष हेतु अंकन 2,44,80,000/–रूपये तथा अनुवर्ती वर्षों में गत वर्ष की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके देय होगा। राज्य सरकार द्वारा वर्णित खनन पट्टे के लिए 05 वर्ष के निमित्त एतदधीन लिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित ... 2 ग्राम ग्राम छपरौली खादर, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत के खसरा/गाटा सं0 ... कुल रकबा 9.570 है0 पांच वर्षो के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने उन्होंने प्रतिभूति स्वरूप अंकन 61,20,000/–रूपये तथा प्रथम वर्ष की किश्त का 20 प्रतिशत

........क्रमश: 3 पर

(योगेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद–बागपत

जिलाधिकारी
बागपत

धनराशि अंकन 48,96,000/–रूपये अग्रिम रूप से राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिये गये पट्टेदार की ओर से भुगतान किये जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किये जाने वाले स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है।

उपखनिज बालू (यमुना नदी) (यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "उपखनिज" कहा गया है, की समस्त खान तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा। जो ऐसी स्वतन्त्रताओं, अधिकारों तथा विशेष अधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो, सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतन्त्रताओं, अधिकार तथा विशेष अधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक 25-10-2023 से 24-10-2028 तक (पांच वर्ष हेतु) की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार की एतद्द्वारा दिए गए पदान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकालने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित स्वामियों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो, और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र :यह समस्त भू–खण्ड, जो जिला बागपत की तहसील बडौत के अन्तर्गत स्थित **ग्राम छपरौली** खादर पर (क्षेत्र तथा क्षेत्रों का विवरण) स्थित है और उसकी भू–कर सर्वेक्षण खसरा संख्या/गाटा संख्या–1/2 है जिसमें कुल क्षेत्रफल 9.570 **है0** क्षेत्रफल है और जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शें में किया गया है और उसे लाल रंग से रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :–

ग्राम छपरौली खादर	उत्तर में गाटा सं0 1/2 का शेष भाग
	दक्षिण में गाटा सख्या 1/2 का शेष भाग
	पूरब में गाटा संख्या 1/2 का शेष भाग
	पश्चिम में गाटा सख्या 1/2 का शेष भाग

क्रमशः 4 पर

(सागर कुमार तिवारी)
अधिकारी
जनपद–बागपत

Scanned with OKEN Scanner

सं0: 202300735016504

पट्टा विलेख/ करारनामा

यही सं0: 1 रजिस्ट्रेशन सं0: 12615 वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1555728.18 स्टाम्प शुल्क- 3112000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1556000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 1556100

श्री ... दयानन्द ... ,
पुत्र श्री ...
व्यवसाय : अन्य
निवासी: यमुनापुरम बुलन्दशहर आधार न0-********2582

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/10/2023 एवं 02:15:19 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

... राय . .
उप निबंधक :बड़ौत
बागपत
25/10/2023

रामदेव .
निबंधक लिपिक
25/10/2023

पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र व सीमाबंधन की आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र का कोआर्डिनेट्स:–

Name of Pillars	Latitude	Longitude
A	29°13'14.6" N	77°08'39.3" E
B	29°13'11.4" N	77°8'33.5" E
C	29°13'21.8" N	77°8'21.33" E
D	29°13'25.7" N	77°8'29.7" E

और जिसे एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है।

भाग–2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित स्वामित्व

स्वामित्व की धनराशि :(1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में उसके/उनके द्वारा हटाये गये उपखनिज बालू (यमुना नदी) के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेगें।

(पंचम अनुसूची)

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के पंचम अनुसूची नियम–27(3) के अनुसार देय धनराशियों के जमा करने का विवरण :–

जमा की जाने वाली धनराशि का माह व धनराशि का प्रतिशत	माहवार देय धनराशि का विवरण				
	प्रथम वर्ष 2023 की किश्त रू0 24480000/–	द्वितीय वर्ष 2024 किश्त रू0 26928000/–	तृतीय वर्ष 2025 किश्त रू0 29620800/–	चतुर्थ वर्ष 2026 किश्त रू0 32582880/–	पंचम वर्ष 2027 किश्त रू0 35841168/–
01. October 20%	रू0 48,96,000/– अग्रिम रूप से जमा	5385600/–	5924160/–	6516576/–	7168234/–
01. November 10%	रू0 24,48,000/–	26,92,800/–	2962080/–	3258288/–	3584117/–
01. December 10%	रू0 24,48,000/	26,92,800/–	2962080/–	3258288/–	3584117/–
01.January 10%	रू0 24,48,000/–	26,92,800/–	2962080/–	3258286/–	3584117/–
01. February 10%	रू0 24,48,000/–	26,92,800/–	2962080/–	3258288/–	3584117/–
01. March 10%	रू0 24,48,000/–	26,92,800/–	2962080/–	3258288/–	3584117/–
01. April 10%	रू0 24,48,000/–	26,92,800/–	2962080/–	3258288/–	3584117/–
01. May 10%	रू0 24,48,000/–	26,92,800/–	2962080/–	3258286/–	3584117/–
01. June10%	रू0 24,48,000/–	26,92,800/–	2962080/–	3258288/–	3584117/–

स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होगा :(2) (इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किश्तों का भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग–102–खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क 01 खनिज रियायत शुल्क और स्वत्व शुल्क सरकारी कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेजी जायेगी।)

स्वामित्वों का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि किसी ज्ञापन पत्र (present) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय स्वामित्व की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा नियत समय के

क्रमशः 5 पर

(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
बागपत

आवेदन सं०: 202300735016504

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 12615 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पटटा दाता: 1

श्री महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा सोमेन्द्र कुमार तिवारी, खनन अधिकारी बागपत

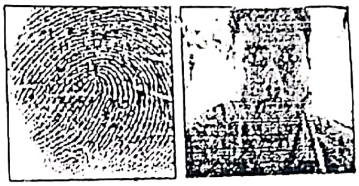

निवासी: बागपत

व्यवसाय: अन्य

पटटा गृहीता: 1

श्री ट क कड2धक्ष्प्र दयानन्द बरगोती, पुत्र श्री हरस्वरुप

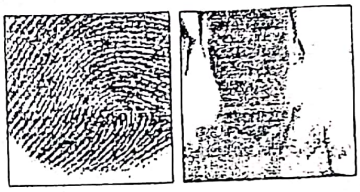

निवासी: यमुनापुरम बुलन्दशहर आधार न0-********2582

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

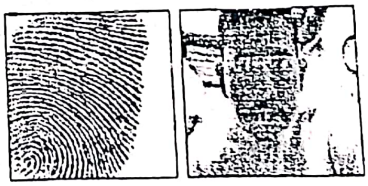

श्री मनोज कुमार , पुत्र श्री लाचारी सिंह

निवासी: यमुनापुरम बुलन्दशहर आधार न0-********2971

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

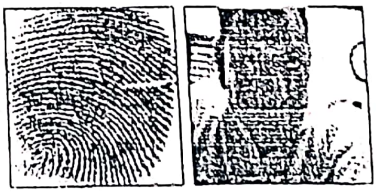

श्री आनन्दपाल , पुत्र श्री अनूप सिंह

निवासी: ग्राम बदरखा आधार न0-********6678

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

... साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

शुभ्रा राय . .

उप निबंधक : बड़ौत

बागपत

25/10/2023

भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रमाण पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसे मालगुजारी का बकाया।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है :(1) यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करें तो राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जायेगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेगें: (2) पट्टेदार उस उपस्थापन–पत्र के आधार पर देय स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक की पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाय) और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने की लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी मशीन संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (convenience) को उखाड़ सकता है/सकतें हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास के अधिक समय तक छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्तीः–(3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात् तीन कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गयी हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न उठाये जाये, तो यह समझा जाएगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गयी और प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना उनकी बिक्री या निस्तारण ऐसी रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

नोटिसः–(4) इस उपस्थापन–पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिये जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप से दिया जायेगा जिसे पट्टेदार ऐसे नोटिस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे/करें, और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो तो प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे पते पर भेजा जाएगा, जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील

क्रमशः 6 पर

(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी

पट्टेदार / पट्टेदारों पर उचित तथा वैध तामील समझी जायेगी और उसके सम्बन्ध में उसके / उनके न तो आपत्ति की जायेगी और न उसे उपाहूत (challenged) किया जाएगा।

अतिरिक्त शर्ते :–

(1) पट्टेदार पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टेदार अपने स्वंय के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(2) पट्टा अभिलेख निष्पादन के दिनांक से एक माह के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।

(3) पट्टा धारक नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए एवं खनन स्थल की निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट / गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट / गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एंव सदैव उसे चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(4) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई0–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एंव चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली 2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(5) पट्टाधारक द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, बागपत के निर्धारित खाते में नियमानुसार देय धनराशि एंव रायल्टी के सापेक्ष आयकर के मद में टी0डी0एस0 जमा करना अनिवार्य होगा।

(6) पट्टाधारक को खनन क्षेत्र में पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(7) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो भी कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाएँ नहीं करेगा।

.......क्रमशः 7 पर

(सोमेन्द्र कुमार)
खान अधिकारी
जनपद–बागपत

जिलाधिकारी
बागपत

Scanned with OKEN Scanner

(8) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(9) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(10) खनन संक्रियाओं में नदी की जलधारा को छोड़कर पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है।

(11) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर उपखनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(12) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा प्रयुक्त वाहनों में उपखनिज की फीडिंग की जायेगी।

(13) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(14) खनन/परिवहन में जन-धन की हानि की समस्त जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।

(15) पट्टेधारक को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 यथा संशोधित एवं सुसंगत शासनादेशों एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों को अक्षरशः पालन करना होगा।

(16) पट्टेधारक स्वीकृत एवं चिन्हांकित खनन क्षेत्र से बाहर किसी भी दशा में खनन कार्य नहीं करेगा, साथ ही मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करेगा।

(17) पट्टेधारक नियमावली 2021 के नियम–75 के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0–12 में जिलाधिकारी और निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने पर अंकन 2,000/–रूपये की शास्ति का भागीदार होगा तथा पट्टेदार की ऐसी चूक, खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।

(18) खनन कार्य करने के दौरान यदि कोई अन्य खनिज/उपखनिज प्राप्त होता है तो उसकी सूचना पट्टेधारक तत्काल जिला कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (उ0प्र0) के क्षेत्रीय कार्यालय एवं निदेशालय को देगा।

(19) पट्टेदार को पट्टाकृत क्षेत्र में खनिज के समुचित विकास हेतु वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु खनिज/उपखनिज का खनन व निकासी करने के उपरान्त क्षेत्र का समतलीकरण कर वहाँ वृक्षारोपण करना होगा।

(20) स्वीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

(21) खनन पट्टा स्वीकृति के पश्चात् भविष्य में वन विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा शर्तों के विपरीत कार्य करने के कारण आपत्ति किये जाने पर उक्त नियमावली 2021 के नियम 61 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

क्रमशः 8 पर

(... कुमार तिवारी)
खान अधिकारी

(22) पट्टेधारक द्वारा खनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग स्वयं के पर बनाया जायेगा। यदि खनिजों के परिवहन हेतु किसी काश्तकार की भूमि से होकर रास्ते का निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित काश्तकार की लिखित सहमति सम्बन्धी अभिलेख जिला कलेक्ट्री कार्यालय, बागपत में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रास्ते के निर्माण में होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(23) खनन स्थल से निकाले गये खनिज पदार्थ का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।

(24) स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि के बाहर कोई अवैध खनन पाये जाने पर उक्त नियमावली 2021 के नियम 61 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

(25) स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर किसी प्रतिबन्धित क्षेत्र (यदि कोई हो) में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन पाये जाने पर नियमानुसार खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(26) स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर निजी भूमि होने की दशा में पट्टाधारक भूमि के स्वामी को नियम–68 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करेगा।

(27) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–35(4) के अनुसार निदेशालय द्वारा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित शर्तों का पालन पट्टेधारक को किया जाना आवश्यक होगा।

(28) निदेशालय के पत्र संख्या–441/एम–228/2017 (खनन नीति।।।) दिनांक 27–06–2019 के अनुपालन में पट्टा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को आन्तरित किये जाने में पट्टेधारक को कोई आपत्ति नही होगी।

(29) पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र में संशोधन आदि यदि आवश्यकता हो का दायित्व स्वयं पट्टाधारक का होगा।

(30) राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के पत्र सं0 810/पर्या0/सीईएए/5005–4451/2020 दिनांक 17.03.2021 में इंगित शर्तो का पालन हेतु पट्टेधारक बाध्य होगा।

(31) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान रखते हुये अन्य शर्ते जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जायेगी पट्टधारक को मान्य होगा।

स्टाम्प शुल्क: स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रतिभूति की धनराशि अंकन 61,20,000/–रूपये प्रथम वर्ष की धनराशि अंकन 2,44,80,000/–रूपये द्वितीय वर्ष की धनराशि अंकन 2,69,28,000/–रूपये तृतीय वर्ष की धनराशि अंकन 2,96,20,800/–रूपये चतुर्थ वर्ष की धनराशि अंकन 3,25,82,880/–रूपये पंचम वर्ष की धनराशि अंकन 3,58,41,168/–रूपये कुल धनराशि अंकन 15,55,72,848/–रूपये होती है, पर 2 प्रतिशत की दर से अंकन 31,11,500/–रूपये का ई–स्टाम्प संख्या IN-UP41149399526001V दिनांक 12.10.2023 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में जारी किया गया है।

.....क्रमशः 9 पर

(सौमन्द्र कुमार तिवारी) अपर जिलाधिकारी
खनन अधिकारी बागपत
जनपद–बागपत

Scanned with OKEN Scanner

इनके साक्ष्य के रूप में यह उपरथापन–पत्र एतद्धीन आई हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

पट्टेधारक द्वारा हस्ताक्षरित

आनन्दपाल

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए
और उनकी ओर से

जिलाधिकारी
बागपत

गवाह

1. आनन्दपाल पुत्र श्री अनूप सिंह
ग्राम व पोस्ट - बदरखा,
तहसील बड़ौत, जनपद - बागपत।

गवाह

2. मनोज कुमार पुत्र स्व० श्री
लाचारी सिंह,
निवासी- 404, आन्ना होम्स, कलोनी
यमुनापुरम, बुलन्दशहर।

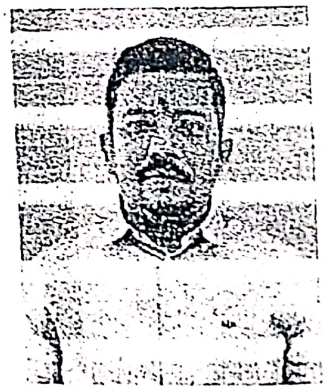

(सोमेन्द्र कुमार अधिकारी)
खान अधिकारी
जनपद - बागपत

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
बागपत।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
बागपत

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -3

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), UTTAR PRADESH)

To,

The -1
DAYACHAND BADGOTI
M. No 5 Nai Break Point Resturant, Bhur Chauraha K Pass, Yamunapur, Bulanshahar U.P. -203001

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/UP/MIN/439838/2023 dated 10-Aug-2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	EC Identification No.	EC23B001UP110342
2.	File No.	8077-7633
3.	Project Type	New
4.	Category	B
5.	Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6.	Name of Project	Proposed Chhaprauli Khadar Ordinary Sand Mining project on Yamuna Riverbed
7.	Name of Company/Organization	DAYACHAND BADGOTI
8.	Location of Project	UTTAR PRADESH
9.	TOR Date	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 07/10/2023

(e-signed)
Ajay Kumar Sharma
Member Secretary
SEIAA - (UTTAR PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

Scanned with OKEN Scanner

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
E-Mail- doeuplko@yahoo.com, seiaaup@yahoo.com
Phone no- 0522-2300541

Reference- MoEFCC Proposal no SIA/UP/MIN/439838/2023 & SEIAA, U.P File no-8077/7633

Sub: Environmental Clearance for Proposed Ordinary Sand mining project on Riverbed of Yamuna River at Gata No. 1/2, Village- Chhaprauli Khadar, Tehsil- Baraut, and District: Baghpat, State- Uttar Pradesh, (Leased Area 9.570 ha.), M/s Royal Construction Company.

Dear Sir,

This is with reference to your application / letter dated 10-02-2023, 13-03-2023, 10-08-2023, 23-08-2023 above mentioned subject. The matter was considered by 777th SEAC in meeting held on 23-08-2023 and 758th SEIAA in meeting held on 19-09-2023.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s Cognizance Research India Pvt. Ltd to SEAC on 23-08-2023.

Project Details Informed by the Project Proponent and their Consultant

The project proponent, through the documents and presentation gave following details about their project –

1. The environmental clearance is sought for Ordinary Sand mining project on Riverbed of Yamuna River at Gata No. 1/2, Village- Chhaprauli Khadar, Tehsil- Baraut, and District: Baghpat, State- Uttar Pradesh, (Leased Area 9.570 ha.), M/s Royal Construction Company.
2. The Terms of Reference in the matter were issued by SEIAA, U.P vide Letter No. 45/Parya/SEIAA/7633/2022, Dated 23/03/2023.
3. The Public Hearing was organized on 12/07/2023 Final EIA report submitted by the project proponent on 10/08/2023.
4. Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1.	On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/439838/2023
2.	File No. allotted by SEIAA, UP	8077/7633
3.	Name of Proponent	M/S Royal Construction Company, Prop. Shri Dayachand Bargoti
4.	Full correspondence address of proponent and mobile No.	R/o M.No. 5, Nai Break Point Restaurant, Bhur Chauraha k pass, Yamunapur, District- Bulandshahar (U.P.)
		Mobile No-
		Email-
5.	Name of Project	Chhaprauli Khadar Ordinary Sand mining project on Riverbed of Yamuna River
6.	Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Gata No. 1/2
7.	Name of River	Yamuna River
8.	Name of Village	Chhaprauli Khadar
9.	Tehsil	Baraut
10.	District	Baghpat
11.	Name of Minor Mineral	Ordinary Sand
12.	Sanctioned Lease Area (in Ha.)	9.570 ha
13.	Max & Min mPL within	

Scanned with OKEN Scanner

14.	Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Sanctioned Mining Lease Area (see table below)
15.	Total Geological Reserves	4,08,354 Cum
16.	Total Mineable Reserves in LOI	2,40,000 Cum/year
17.	Total Proposed Production	12,00,000 cum in 5 Years
18.	Proposed Production/year	2,40,000 Cum/year
19.	Sanctioned Period of Mine lease	05 years
20.	Method of Mining	Open Cast Semi-mechanized Method
21.	No. of working days	260 days
22.	Working hours/day	8 hrs
23.	No. of workers	54
24.	No. of vehicles movement/day	70
25.	Ultimate Depth of Mining	2.90 m
26.	Nearest metalled road from site	2.30 km (approx)
27.	Water Requirement	(see table below)
28.	Name of QCI Accredited Consultant with QCI No and period of validity.	Cognizance Research India Pvt. Ltd. 1922, validity= 10, September 2023
29.	Any litigation pending against the project or land in any court	No
30.	Details of 500 m Cluster Map & certificate issued by Mining Officer	Yes, certified 342/Kha. li./2022-23 Dated- 10.01.2023
31.	Details of Lease Area in approved DSR	Yes, given in the DSR 374/M 0-228/2017 (Khanan Niti)- DSR
32.	Proposed CER cost/year	Rs 2,00,000/-
33.	Proposed EMP cost/year	Recurring Cost- 8,88,000/-
34.	Length and breadth of Haul Road	Length: 500 m, width: 6 m
35.	No. of Trees to be Planted	9500 plants

Sanctioned Mining Lease Area (item 14):

Pillar No.	Latitude	Longitude
A	29°13'14.6"N	77°08'39.3"E
B	29°13'11.4"N	77°08'33.5"E
C	29°13'21.8"N	77°08'21.33"E
D	29°13'25.7"N	77°08'29.7"E

Water Requirement (item 27):

PURPOSE	REQUIREMENT (KLD)
Drinking	0.54
Suppression of dust	3.0
Plantation	19.0
Others (if any)	0.54
Total	23.08

5. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
6. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
7. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
8. There is no litigation pending in any court regarding this project.
9. The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee Meeting (SEAC) held on 23-08-2023 the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in its Meeting held 19-09-2023 and decided to grant the Environment [illegible] project for collection

Scanned with OKEN Scanner

40,000 Cum/year for lease area of 9.570 ha subject to effective implementation of the following General Conditions and specific conditions:-

General condition:

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any change in mining area, khasra numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology, modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended).
4. Precise mining area will be jointly demarcated at site by project proponent and officials of Mining/Revenue department prior to starting of mining operations. Such site plan, duly verified by competent authority along-with copy of the Environmental Clearance letter will be displayed on a hoarding/board at the site. A copy of site plan will also be submitted to SEIAA within a period of 02 months.
5. Mining and loading shall be done only within day hours' time.
6. No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment.
7. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take-care of dust generated during mining operation. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
8. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.
9. Parking of vehicles should not be made on public places.
10. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
11. No wildlife habitat will be infringed.
12. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
13. It shall be ensured that mining operation of Sand/Moram will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.
14. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting. A report on the same, vetted by the competent authority shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within 02 months.
15. Primary survey of flora and fauna shall be carried out and data shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months.
16. Hydro-geological study shall be carried out by a reputed organization/institute within six months and establish that mining in the said area will not adversely affect the ground water regime. The report shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months. In case adverse impact is observed /anticipated, mining shall not be carried out.
17. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, UPPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.
18. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects/tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such program me. The project proponent and income generating

Scanned with OKEN Scanner

19. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Horticulture Officer.
20. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil, if any, and the top soil should be utilized for green cover/tree plantation.
21. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
22. An Environmental Audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the SEIAA.
23. The District Mining Officer should quarterly monitor compliance of the stipulated conditions. The project proponent will extend full cooperation to the District Mining Officer by furnishing the requisite data/information/monitoring reports. In case of any violations of stipulated conditions the District Mining Officer will report to SEIAA.
24. The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions including results of monitored data (both in hard & soft copies) to the SEIAA, the District Officer and the respective Regional Office of the State Pollution Control Board by 1st June and 1st December every year.
25. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad/ Municipal Corporation and Urban Local Body.
26. Transportation of materials shall be done by covering the trucks / tractors with tarpaulin or other suitable mechanism to avoid fugitive emissions and spillage of mineral/dust.
27. Waste water, from temporary habitation campus be properly collected & treated before discharging into water bodies the treated effluent should conform to the standards prescribed by MoEF/CPCB.
28. Measures shall be taken for control of noise level to the limits prescribed by C.P.C.B.
29. Special Measures shall be adopted to protect the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of Village roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out by the project proponent regularly at his own expenses.
30. Measure for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion, if any, shall be carried-out with geo textile matting or other suitable material.
31. Under corporate social responsibility a sum of 5% of the total project cost or total income whichever is higher is to be earmarked for total lease period. Its budget is to be separately maintained. CER component shall be prepared based on need of local habitant. Income generating measures which can help in upliftment of poor section of society, consistent with the traditional skills of the people shall be identified. The programme can include activities such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, free distribution of smokeless Chula etc.
32. Possibility for adopting nearest three villages shall be explored and details of civic amenities such as roads, drinking water etc proposed to be provided at the project proponent's expenses shall be submitted within 02 months from the date of issuance of Environment Clearance.
33. The funds earmarked for environmental protection measures should be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Year wise expenditure should be reported to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow, SEIAA, U.P and UPPCB.
34. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during Public Hearing shall be submitted to the District mines Officer, concern Regional Officer of UPPCB and SEIAA within 02 months.
35. Environmental clearance is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent authority, if applicable to this project.
36. The proponent shall observe every 15 day for nesting of any turtle in the area. Based on the observations so made, if turtle nesting is observed, necessary safeguard measures shall be

Scanned with OKEN Scanner

created amongst the workers about the nesting sites so that such sites, if any, are identified by the workers during operations of the mine for taking required safeguard measures. In this regards the safety notified zone should be left so that the habitat/nesting area is undisturbed.

37. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro geological regime of the surrounding area shall not be affected.
38. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent Authorities for withdrawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), required for the project.
39. Appropriate mitigative measures shall be taken to prevent pollution of the river in consultation with the State Pollution Control Board. It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles used for transportation.
40. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
41. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. (MoEF circular Dated : 22-09-2008 regarding stipulation of condition to improve the living conditions of construction labour at site).
42. Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
43. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad/ Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
44. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of environmental clearance conditions and shall also be sent to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow by e-mail.
45. The green cover development/tree plantation is to be done in an area equivalent to 20% of the total leased area either on river bank or along road side (Avenue Plantation).
46. Debris from the river bed will be collected and stored at secured place and may be utilized for strengthen the embankment.
47. Safety measures to be taken for the safety of the people working at the mine lease area should be given, which would also include measure for treatment of bite of poisonous reptile/insect like snake.
48. Periodical and Annual medical checkup of workers as per Mines Act and they should be covered under ESI as per rule.

Specific Conditions:

1. District Mining Officer shall ensure that if mineable quantity mentioned in LOI is amended as per replenishment study report the project proponent shall seek amended/fresh EC.
2. Directions/suggestions given during public hearing and commitment made by the project

Scanned with OKEN Scanner

A certificate from Forest Department shall be obtained that no forest land is involved in mining or as a route and if forest land is involved the project proponent shall obtain forest clearance and permission of Central and State Government as per the provisions of Forest (conservation) Act, 1980 and submit before the start of work.

4. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora fauna etc.
5. If the proposed project is situated in notified area of ground water extraction, where creation of new wells for ground water extraction is not allowed, requirement of fresh water shall be met from alternate water sources other than ground water or legally valid source and permission from the competent authority shall be obtained to use it.
6. Project Proponent should submit action plan for carrying out plantation at least @1,000 plants / ha of lease area. In this case, PP should prepare a plan, duly approved either by Forest Department or district plantation committee, for planting at least 10,000 plants, either on government land or community land, within a periphery of 5 km from the boundary of the lease area along with provision for maintenance for 5 years. Survival of plants should not be less than the survival rate notified by Uttar Pradesh Forest Department otherwise it will be treated as violation of EC condition.
7. In consultation with District Environment Authority or an Authority nominated by concerned DM, project proponent will prepared a conservation and management plan for rejuvenation and management of water bodies having total surface area of more than 50 ha. Funds for the same will be kept in a separate bank account and six monthly compliance status will be presented by project proponent before the nominated authority in the District.
8. Department of Geology and Mines, Government of Uttar Pradesh and / or concerned district administration, before releasing the security deposit to Project Proponent will ensure that Project Proponent has fully complied with the EC conditions. Non-compliance, if any, should be reported to UPSPCB for appropriate legal action and recovery of compensation.
9. Any application for transfer of this EC, during its validity period unless it is cancelled by a competent authority, has to be necessarily accompanied with status of compliance of EC conditions duly certified by IRO, MoEFCC, GoI, Lucknow.
10. Directorate of Geology and Mining will ensure conduct of replenishment study from reputed institution for subsequent years in compliance of Hon'ble NGT orders. The quantity mentioned in LoI or quantity mentioned in replenishment study, whichever is less, would be maximum quantity which project proponent may extract. It will be ensured by District Administration and Geology and Mining Department.
11. NOC from Irrigation Department/ Concerning Authority regarding river bed mining to be obtained before start of mining activity.
12. Project proponent has committed to plant 1000 number of trees/hectare. The project proponent/consultant if desires may approach to concerned District Forest Authority to plant 1000 trees/ha on a land available to the Forest Department. The project proponent will deposit the required amount for this entire plantation work (including its maintenance and security) to the Forest Department.
13. The project proponent shall install solar light in their site office.
14. During the submission of 6 monthly compliance reports, the project proponent should make sure that the periodically taken site photographs should also be annexed along with the compliance report.
15. Preference should be given to indigenous local species as per the consultation of the local district Forest Officer.
16. Link Road from the quarry site to the main road shall be constructed as an all-weather road with blacktopping and maintained by the project proponent.

Scanned with OKEN Scanner

17. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored. Suitable measures shall be taken for proper maintenance of vehicles used in a quarry operation and transportation.
18. The project proponent should explore the possibilities of rainwater harvesting.
19. Agreement/ Consent between project proponent and competent authority/ landowner for haulage road from lease site to link road.
20. Latest technology (water sprinklers/ tankers) to be adopted for mitigating dust at source points in lease area and haulage road during operational activity/vehicular movement.
21. As per the proposed plan, plantation with area specific plant species, number of plants to be planted and report of green belt development to be submitted to the concerning department
22. Water requirement details along with source of water and the permission/ agreement with the concerning authority/ water supplying agencies to be submitted.
23. Submit the Hydrological study report of lease area that the quantity given in LoI will be mined without affecting the geo-hydrology of the River.
24. The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period/mining plan whichever is less.
25. At the time of operation, project proponent will comply with all the guidelines issued by Government of India/State Govt./District Administration related to Covid-19.
26. Environment management in according to environmental status and impact of the project.
27. During the school opening and closing time transportation of minerals will be restricted.
28. Selection of plants for green belt should be on the basis of pollution removal index. Project proponent should ensure survival of tree saplings. Mortality should be replaced from time to time.
29. No mining activity should be carried out in-stream channel as per SSMMG, 2016.
30. Pakkamotorable haul road to be maintained by the project proponent.
31. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
32. Permission from the competent authority regarding evacuation route should be taken.
33. One month monitoring report of the area for air quality, water quality, Noise level. Besides flora & fauna should be examined twice a week and be submitted within 45 days for a record.
34. Provision for cylinder to workers should be made for cooking.
35. The capacity of trucks/tractor for loading purpose will be in tonnes as per Transport Department applicable norms and standard fixed by the Government.
36. Approach road kaccha is to be made motarable and tree saplings to be planted on both sides of the road. Width of the haul road shall be more than 6 meter.
37. Indigenous plants should be planted according to CPCB guidelines and in consultation with local Divisional Forest Officer.
38. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer.
39. Provision for two toilets and hand pumps should be made at mining site.
40. Drinking water for workers would be provided by tankers.
41. Mining should be done by Bar scalping methods extraction (typically 0.3 -0.6 m or 1 - 2 ft) as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
42. A buffer/safe zone shall be maintained from the habitation as per mining guidelines.
43. Corporate Environmental Responsibility (CER) plan shall be prepared by the project proponent and the details of the various heads of expenditure to be submitted as per the guidelines provided in the recent CER notification No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018.
44. Health/Insurance card, Medical claim, regular health check-up camps, facilities shall be provided to the regular/temporary/Contractual or any base workers. Copy of receipt shall be produced to the Directorate of Environment along with the compliance report.

Scanned with OKEN Scanner

45. Measure for conservation of water through rainwater harvesting and cleaning and maintenance of natural surface water bodies of the nearby areas may be considered as one of the activity in CER.
46. The excavated mining material should be carried and transported in such a way that no obstruction to the free flow of water takes place. Suitable measure should be taken and details to be provided to concern Department.
47. Submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.
48. The project proponent shall ensure that if the project area falls within the eco-sensitive zone of National park/ Sanctuary prior permission of statuary committee of National board for wild life under the provision of Wildlife (Protection) Act, 1972 shall be obtained before commencement of work.
49. If in future this lease area becomes part of cluster of equal to or more than 05 ha. then additional conditions based on the EIA shall be imposed. The lease holder shall mandatorily follow cluster conditions otherwise it will amount to violation of E.C. conditions. If the certificate related to cluster provided by the competent authority is found false or incorrect then punitive actions as per law shall be initiated against the authority issuing the cluster certificate.
50. Project falling within 10 KM area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
51. To avoid ponding effect and adverse environmental conditions for sand mining in area, progressive mining should be done as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
52. In case it has been found that the E.C. obtained by providing incorrect information, submitting that the distance between the two adjoining mines is greater than 500mt. and area is less than 05 ha, but factually the distance is less than 500 mt and the mine is located in cluster of area equal or more than 05 ha, the E.C issued will stand revoked.
53. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer which shall form the basis for midterm review of conditions of Environmental Clearance.
54. The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to orders). Heavy machine such as excavator, scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be involved at any stage.
55. It shall be ensured that there shall be no mining of any type within 03 m or 10% of the width which-ever is less, shall be left on both the banks of precise area to control and avoid erosion of river bank. The mining is confined to extraction of sand/moram from the river bank only.
56. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bank material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.
57. The project proponent shall adhere to mining in conformity to plan submitted for the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked (Non mining area), distance from the bridges etc. It shall be ensured that no mining shall be carried out during the monsoon season.
58. The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
59. The project proponent will provide personal protective equipment (PPE) as required, also provi adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examinatio of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained. For th purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followe

Scanned with OKEN Scanner

60. The critical parameters such as PM10, PM2.5, SO2 and NOx in the ambient air within the impact zone shall be monitored periodically. Further, quality of discharged water if any shall also be monitored [(TDS, DO, pH, Fecal Coliform and Total Suspended Solids (TSS)].
61. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads.
62. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
63. The extended mining scheme will be submitted by the proponent before expiry of present mining plan.
64. Four ambient air quality-monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring PM10, PM2.5, SO2 and NOx. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board.
65. Common road for transportation of mineral is to be maintained collectively. Total cost will be shared/worked out on the basis of lease area among users.
66. Proponent will provide adequate sanitary facility in the form of mobile toilets to the labours engaged for the project work.
67. Solid waste material viz., gutkha pouchs, plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately storage in bins and managed as per Solid Waste Management rules.
68. Natural/customary paths used by villagers should not be obstructed at any time by the activities proposed under the project.
69. Digital processing of the entire lease area in the district using remote sensing technique should be done regularly once in three years for monitoring the change of river course by Directorate of Geology and Mining, Govt. of Uttar Pradesh. The record of such study to be maintained and report be submitted to Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow, SEIAA, U.P. and UPPCB.
70. The project authorities shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the SEIAA at http://www.seiaaup.in and a copy of the same shall be forwarded to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow, CPCB, State PCB.
71. The MoEF&CC/SEIAA or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
72. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
73. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 11 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997.
74. Waste water from potable use be collected and reused for sprinkling.
75. A width of not less than 50 meter or 10% width of river can be restricted for mining activities from river bank.A condition can be imposed that mining will be done from river activities from river bank.

You shall also ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as

Scanned with OKEN Scanner

deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

The above stipulated conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along-with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provisions of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14/09/2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

Copy, through email, for information and necessary action to –

1. Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (email – psforest2015@gmail.com)
2. Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 3rd Floor, Prithvi-Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email – sudheer.ch@gov.in)
3. Deputy Director General of Forests (C), Integ rated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020 (email – rocz.lko-mef@nic.in)
4. District Magistrate, Bagpat.
5. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (email – ms@uppcb.com)
6. Copy to Web Master for uploading on PARIVESH Portal.
7. Copy for Guard File.

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

Scanned with OKEN Scanner

पट्टेदार की स्वतन्त्रताएं, शक्तियाँ और विशेषाधिकार

41–नियम 42 में उल्लिखित निर्बन्धन और शर्तो और भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अध्यधीन इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित स्वतन्त्रता, शक्ति और विशेषाधिकार होंगे :–

(क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खान की खोज करना, उस खनिज का जिसके लिये पट्टा हो, वेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बरमें द्वारा सूराख करना (drill) या उसे लब्ध करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।

(ख) उक्त भूमि में कोई गड्ढा खोदना, कूपक (Shafts) ढाल (inclines) पशु मार्ग (drifs) समतल, जलमार्ग (Water Ways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।

(ग) पट्टेदार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार नदी की जल धारा को छोड़कर मशीन की सहायता से खनन कर सकता है और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिये भी मशीन का प्रयोग कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से पट्टेदार भूमि पर किसी मशीनरी, संयंत्र प्रसाधन, फर्श, भट्ठियां, ईंट भट्ठों, कार्यशाला, मालगोदाम और समान प्रकार के अन्य भवनों का परिनिर्माण तथा निर्माण कर सकता है।

(घ) उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना।

(ङ) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सड़क संबंधी सामान तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईंटों या खपरैल (tiles) निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान, ईट या खपरैलों को न बेचना।

(च) उक्त भूमि की सतह के पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन या किये गये कार्यो और औजारों (tools), सज्जा (equipment), मिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थों का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना, और

(छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 42 के खण्ड (घ) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियां (under growth) और घनी झाड़ी (brushwood) को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खड़े या पाये गये वृक्षों या इमारती लकड़ी के वृक्षों को गिराना और इसका उपयोग करना:

प्रतिबंध यह है कि जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये और उपयोग में लाये गये किन्हीं वृक्षों या इमारती लकड़ियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिये कह सकता है जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किया जाय।

(ज) किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रिया के बाधित होने की स्थिति में जिला अधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आगामी किस्त के सापेक्ष बाधित अवधि के दौरान संदेय किस्त के समतुल्य धनराशि का समायोजन संदेय देयों से आनलाईन करेगा।

पट्टेदार की स्वतन्त्रताओं शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं

42–पट्टाधारक नियम 41 में उल्लिखित स्वतन्त्रताओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :–

(क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी –

Scanned with OKEN Scanner

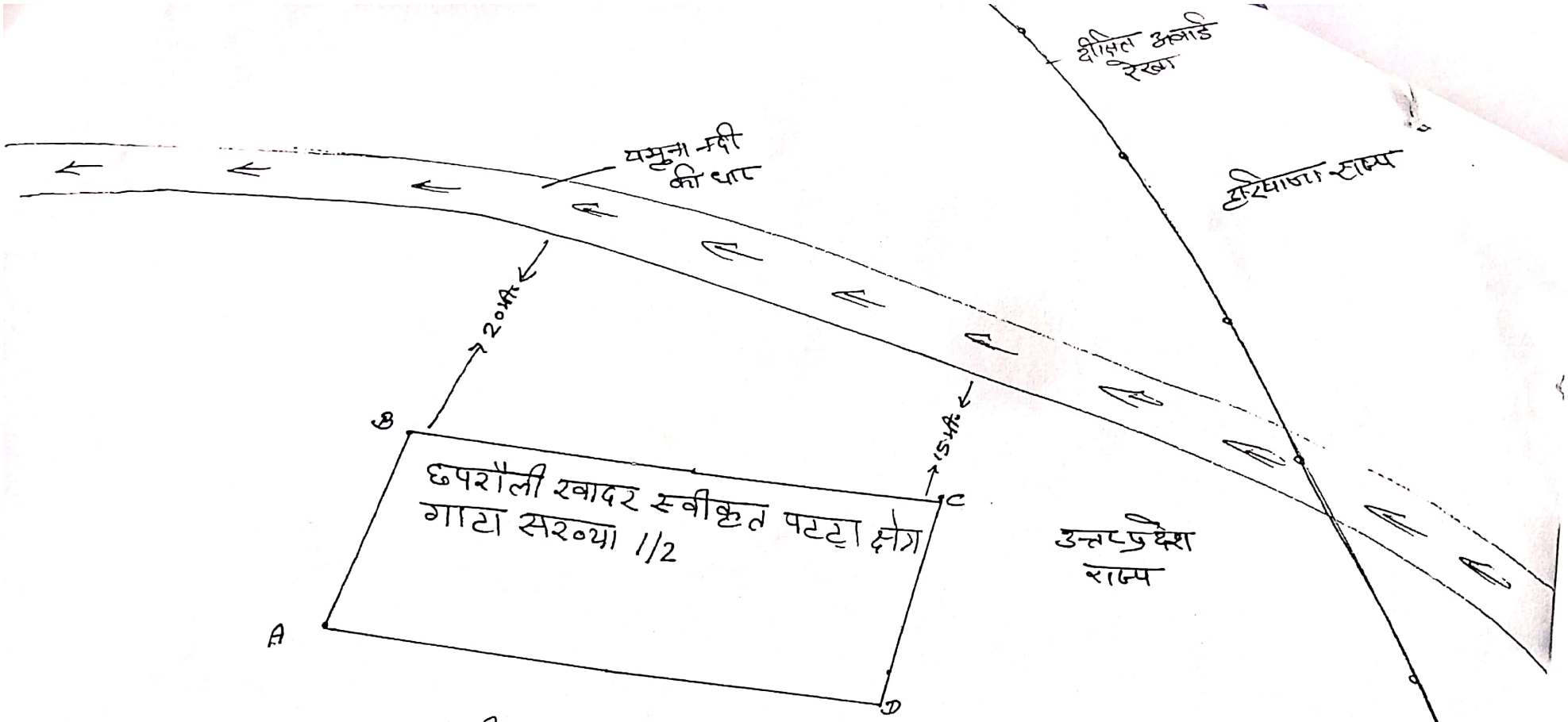

संलग्नक-5

ग्राम छपरौली खादर गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 9.570 हे० में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बिन्दु A B C D को पट्टा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र बिन्दु A B C D के अन्दर बालू खनन/परिवहन किया जा रहा है। वर्तमान में यमुना नदी की धारा से B बिन्दु लगभग 20 मीटर तथा C बिन्दु लगभग 15 मीटर की दूरी पर है। नदी की धारा को ना तो रोका गया और ना ही परिवर्तित ना किया गया है।

13/3/024
मोनू
सर्वे लेखपाल

13/3/024
नन्द किशोर
सर्वे कानूनगो